आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 29.09.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे।
- मध्योत्तर अंडमान के कुछ पंचायतों में सदस्यों की सीट के उप–चुनाव को देखते हुए आज और एक अक्तूबर को संबंधित क्षेत्रों में ड्राई–डे घोषित किया गया है।
- ज़िला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया।
- श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद क्षेत्र में भीख मांगने वालों के विरूद्ध अभियान की शुरूआत की गई है।
- खेलो इंडिया योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए दो नए खेलो इंडिया केन्द्रों को स्थापित करने की स्वीकृति मिली है।

<><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर 'मन की बात' कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात कार्यक्रम की एक सौ चौदहवीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और newsonair मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू–ट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित करेगा।

<><><><><><>

ग्राम पंचायत पर्णशाला में रामपुर–दो निर्वाचन क्षेत्र, रंगत ग्राम पंचायत में रंगत–दस और दशरथपुर ग्राम पंचायत में दशरथपुर–तीन में सदस्यों के लिए आज उप–चुनाव कराया जाएगा और एक अक्तूबर को मतगणना होगी। इस कारण आज और एक अक्तूबर को इन क्षेत्रों में ड्राई–डे घोषित किया गया है। सभी से इसका पालन करने को कहा गया है।

<><><><><><>

ज़िला प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत स्थानीय बुनियादी ढांचे और सतत विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में नमूनाघर ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के प्रधान ने कई प्रमुख स्थानीय मुद्दों को उठाया, जिसमें सड़क की खराब स्थिति, अनियमित बिजली आपूर्ति, जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता शामिल है। इसके अलावा उन्होंने मछुआरा कॉलोनी में सामुदायिक हॉल में शौचालय निर्माण, जंगलों के पास के क्षेत्रों में बिजली के लाईनों तथा सड़कों के लिए बफर ज़ोन की स्थापना, मीठाखाड़ी में फ्लोटिंग जेट्टी और खेल के लिए मैदान की स्थापना और नमूनाघर में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विकास के साथ कई अन्य मुद्दों पर भी ज़िला उपायुक्त का ध्यान आकर्षित किया। ज़िला उपायुक्त ने इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का आश्वासन दिया।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और बैठकों के बाद एक ठोस मुद्दों को लेकर संबंधित मंत्रालयों से ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए सांसद बिष्णु पद रे ने थिंक टैंक का गठन करने का प्रस्ताव किया है। समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर रोज़गार कौशल मुखी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जहाजरानी और राजस्व से जुड़े लोगों को शामिल कर इनसे सुझाव और विचार आमंत्रित किया जाएगा। नागरिक, उड्डयन, कृषि, खेल, पर्यटन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। स्वेच्छा से जो लोग सांसद के इन प्रयासों में योगदान देना चाहते हैं, वे फोन संख्या नौ चार तीन चार दो छः एक पांच शून्य दो पर डायल कर जानकारी दे सकते हैं। डाक के माध्यम से भी लोग अपने विचार सांसद के ई–मेल आई डी पर या राजनिवास के निकट स्थित सांसद कार्यालय में भी दे सकते हैं।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान ज़िले में वाणिज्यिक परिसरों में बाल श्रम का पता लगाने और उनके बचाव तथा पुनर्वास के लिए अभियान चलाया गया। सहायक आयुक्त मुख्यालय आशीष जून के नेतृत्व में मायाबंदर तहसील के विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। एक सौ बत्तीस के करीब ऐसे परिसरों का निरीक्षण हुआ, जहां एक भी बाल श्रम का मामला सामने नहीं आया। टीम के सदस्यों ने कारोबारियों और कर्मचारियों के बीच बाल श्रम कानूनों के बारे में जागरूकता उत्पन्न की।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद क्षेत्र में उग्रवाद और भीख मांगने वालों के विरूद्ध अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य भीख मांगने वाले गरीब और कमजोर तबके के लोगों तथा परिवारों की पहचान कर उनके लिए पुनर्वास और एक बेहतर भविष्य प्रदान करना है। यह पहल ज़िला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग, नगरपालिका परिषद, राजस्व विभाग और सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से शुरू की गई है। इसके लिए गठित टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे जरूरमंद लोगों की पहचान कर उन्हें उनके मूल निवास स्थानों या घरों पर लौटने के लिए सहायता प्रदान की। भीख माँगने वाले बच्चों, महिलाओं और अलग–अलग दिव्यांगजनों की सुरक्षा और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया। दल ने दुकानदारों, परिवहन संचालकों और लोगों के साथ बात कर भीख मांगने के किसी भी मामले के बारे में बताने का अनुरोध किया। आम जनता से भी आह्वान किया गया है कि वे सूचना या कार्रवाई के माध्यम से मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। लोग जिला नियंत्रण कक्ष संख्या एक शून्य सात पांच या बाल हेल्पलाइन संख्या एक शून्य नौ आठ पर भी जानकारी दे सकते हैं।

<><><><><><><>

कुपोषण मुक्त भारत अभियान के तहत गैर सरकारी संगठन विद यू की ओर से हाल ही में विम्बर्लीगंज के लम्बा पहाड़ सामुदायिक हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गैर सरकारी संगठन विद यू और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विद यू की अध्यक्षा वी के मरियम बीबी ने आई सी डी एस परियोजना फरारगंज के तहत चालीस कुपोषित बच्चों को पौष्टिक किट का वितरण किया।

<><><><><><><>

हिन्दी पखवाड़ा मनाए जाने के सिलसिले में सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजभाषा के नोडल अधिकारियों और इससे सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए आयोजित कार्यशाला में राजभाषा सचिव डॉ. अनिल अग्रवाल ने सभी से अनुरोध किया कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इस वर्ष हम हिन्दी दिवस की हीरक जयंती मना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें कार्यालयों में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग कर शत–प्रतिशत सरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। राजभाषा के उप–सचिव राजेन्द्र इंदवार ने हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सभी से अनुरोध किया।

इस बीच, नेहरू युवा केन्द्र श्री विजयपुरम की ओर से कल एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभाषा उप–सचिव मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने संबोधन में सरकारी कार्यों में हिन्दी के उपयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी अजय सिंह ने

पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से हिन्दी के नियमों और अधिनियमों के बारे में बताया। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पत्र, निबंध और कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

<><><><><><><>

खेलो इंडिया योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के लिए दो नए खेलो इंडिया केन्द्रों को स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी की अध्यक्षता में सैंतालीसवें विभागीय परियोजना स्वीकृत समिति की हाल ही में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया, जो दो नए खेलो इंडिया केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, उनमें एक आई आर बी एन पोर्ट मोट में बॉक्सिंग के लिए और दूसरा पुलिस लाईन में सशस्त्र पुलिस इकाई में कयाकिंग के लिए होगी। इन केन्द्रों के खुल जाने से देश में अंडमान निकोबार पुलिस पहली ऐसी पुलिस होगी, जिनके परिसर में खेलो इंडिया केन्द्र खुलेंगे। इन केन्द्रों में पूर्व एथलिटों द्वारा आम जनता को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से अंडमान निकोबार पुलिस को प्रशिक्षण के लिए अनुदान भी दिया जाएगा ।

<><><><><><><>